आत्मघाती पाकिस्तान

भारत और अन्य पड़ोसी देशों को अस्थिर करने का उद्देश्य पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति का आधारभूत पहलू है. बीते सात दशकों में वहां शासन पर पाकिस्तानी सेना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा है. सेना ने कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ द्वारा समूचे दक्षिणी एशिया में आतंकियों, अलगाववादियों, तस्करों और अपराधियों का बड़ा संजाल बनाया है. भारत और अफगानिस्तान ने लगातार इसकी शिकायत की है. इस नेटवर्क का विस्तार इन दो देशों के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी है. यहां तक कि यूरोप और अमेरिका में हुई अनेक घटनाओं में पाकिस्तान-समर्थित आतंकी और चरमपंथी गिरोहों का हाथ होने के मामले सामने आये हैं. पाकिस्तान के भीतर भी अपने वर्चस्व को बनाने-बचाने के लिए आइएसआइ ने विभिन्न हिस्सों में आतंकी समूहों को पाला-पोसा है. पिछले साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ऐसे समूहों की सूची में पाकिस्तान में सक्रिय 139 संगठनों का नाम है. इनमें अल-कायदा के सरगना अल-जवाहिरी से लेकर तहरीके-तालिबान, लश्करे-तैयबा, जैशे-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क से लेकर दाऊद इब्राहिम तक शामिल हैं. इन गिरोहों में से कुछ कश्मीर में और कुछ अफगानिस्तान में वारदातों को अंजाम देते हैं तथा अन्य समूह पाकिस्तान के भीतर अल्पसंख्यकों, उदारवादी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों को निशाना बनाते रहते हैं. आतंकवाद को राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की पाकिस्तानी राजकीय नीति का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है. आज पाकिस्तान सामाजिक रूप से टूटा हुआ और आर्थिक तौर पर कंगाल देश है. साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक, साल 2000 से अब तक आतंकी घटनाओं में वहां 63,724 मौतें हो चुकी हैं. इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक ये गिरोह सक्रिय हैं. अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार, 2010 तक पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक थी. विभिन्न देशों से मिली वित्तीय मदद और व्यापक आर्थिक विषमता जैसे कारकों का संज्ञान लेते हुए भी कहा जा सकता है कि उसके पास आर्थिकी को पटरी पर रखने के मौके थे. परंतु, पाकिस्तानी सत्ताधीश तो धार्मिक चरमपंथियों को बढ़ावा देने तथा पड़ोसियों के विरुद्ध छद्म युद्ध करने में लगे हुए थे. अनेक आधिकारिक अध्ययनों ने इंगित किया है कि अस्सी के दशक के बाद से आतंकवाद ने अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है. खुद पाकिस्तानी आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2001 के बाद से आतंक से लड़ने में 123 बिलियन डॉलर की चपत लगी है. बीते चार दशकों में निवेश और सहायता में भी लगातार गिरावट दर्ज की गयी है. इन तथ्यों के बावजूद सरकारों ने आतंक को प्रश्रय देने की नीति पर पुनर्विचार नहीं की है. यह रवैया एक राष्ट्र-राज्य के रूप में उसके अस्तित्व के लिए ही आत्मघाती हो गया है.

पाक सरकारों ने आतंक को प्रश्रय देने की नीति पर पुनर्विचार करने की कोशिश नहीं की है. यह रवैया एक राष्ट्र-राज्य के रूप में उसके अस्तित्व के लिए ही आत्मघाती हो गया है.

भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा

मे. ज. जीडी बख्शी
सेवानिवृत्त सेना अधिकारी
delhi@prabhatkhabar.in

पिछले तीस साल से पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ रखी है. इसमें अस्सी हजार के करीब भारतीय नागरिकों और सैनिकों ने अपनी जान गंवायी है. उसकी हर कायरतापूर्ण गतिविधियों पर हमें जवाबी कार्रवाई नहीं करने दी गयी और हमें बरगलाया गया कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और अगर हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो वह हम पर बम छोड़ देगा. यह सब अमेरिकी दबाव के कारण होता रहा है और हम पाकिस्तान की दहशतगर्दी को तीन दशक से झेलते रहे हैं. उस वक्त अमेरिका का बहुत चहेता देश पाकिस्तान ही था और तब वह अफगानिस्तान में पाकिस्तान से मदद चाहता था. और हमारी सरकारें अमेरिकी आदेशों पर चलती रहीं. हमारे विदेश मंत्रालय और शांति का राग अलापनेवालों ने यह फैसला कर लिया था कि भारत को बरबाद हो जाने देंगे, लेकिन जंग नहीं होने देंगे. हम तो अहिंसावादी हैं, गांधीवादी हैं. लेकिन, अब भारत के लोग कुर्बानियां दे-देकर तंग आ चुके हैं. अब हमें गांधीवाद महंगा पड़ रहा है. अब हम उनके गांधीवाद के लिए और जान नहीं देंगे, अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान को करारा से करारा जवाब दे. सब्र का बांध टूट चुका है.

अब हमारे देश में आगामी समय में कोई भी सरकार हो, जो वोट हासिल करके बनती है, उसे अब अपनी सख्त प्रतिक्रिया देनी होगी और पाकिस्तान की हर छोटी कार्रवाई का बड़े हमले से जवाब देना होगा. हम अब डरनेवाले नहीं हैं. पिछले दिनों भारत ने एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया है और वह दिन भारतीय सेना के लिए गर्व का दिन था, तो देश के लिए सिर ऊंचा करनेवाला दिन था. हमारा मिराज जहाज पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर गोले दागकर लौट आया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया. वह बहुत ही प्रोफेशनल एयर स्ट्राइक थी. हमने तो सिर्फ आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका जवाब देकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि जैशे-मुहम्मद उसकी सेना का हिस्सा है. पाकिस्तान ने हमारी सेना पर हमला किया है और हमारे जहाज को मार गिराया है. हालांकि, इसमें उसका भी एक जहाज मार गिराया गया है. पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि भारत अगर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर हमला करेगा, तो वह भारतीय सेना पर हमला करेगा. इससे बड़ा युद्ध का ऐलान नहीं हो सकता, जो पाकिस्तान ने किया है.

हमने पुलवामा का बदला ले लिया है, लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे. हमें मालूम है कि पाकिस्तान नहीं मानेगा, वह फिर कोई न कोई हरकत करेगा. इसलिए मैं कहता हूं कि दो-दो हाथ करके अब इस मसले का हल हो ही जाना चाहिए और यह निश्चित कर लेना चाहिए कि अब किसी भी हाल में हम हमले के लिए तैयार रहेंगे. लेकिन, पाकिस्तान के छद्मयुद्ध को अब बरदाश्त नहीं किया जायेगा. इसके लिए हमें सेना को फ्रीहैंड देना होगा और शांति का राग अलापनेवालों का सुर बिगाड़ देना होगा. यह बहुत बड़ी विडंबना और दुख की बात है कि तीस साल तक हमने कुछ नहीं किया. इसलिए अब हमें इस मसले को हल करके ही दम लेना चाहिए. पाकिस्तान से बातचीत करने को कोई फायदा नहीं है. क्योंकि आज वह बातचीत को तैयार है, कुछ दिन बाद फिर वहां से कोई आतंकी हमला हो जायेगा और हमारे जवान मारे जायेंगे. पाकिस्तान यही तो करता आ रहा है सत्तर साल से.

अब देश को यह फैसला करना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है. क्या हमें सिर्फ पुलवामा का बदला लेना है या बीते तीस वर्षों में जान गंवाये सारे लोगों का बदला लेना है? तय करना होगा कि यह बदला किस पैमाने पर लिया जायेगा?

पाकिस्तान ने हमारे एक पायलट को पकड़ लिया था. मैंने कहा था कि पाकिस्तान को उसे छोड़ना ही होगा. प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाक संसद में ऐलान किया कि वह हमारे पायलट को रिहा करेंगे. जाहिर है, यह तो होना ही था. यह हमारी बड़ी जीत है.

विदेश मंत्रालय की वजह से ही पिछले तीस साल से सेना के हाथ बंधे हुए हैं. सेना जब भी कोई एक्शन लेना चाहती है, तब विदेश मंत्रालय बातचीत करके मामले को शांत कर देता है और पाकिस्तान अपनी मनमानी करने में व्यस्त हो जाता है. सेना को अपना काम करने ही नहीं देते ये लोग. आज हमारे रक्षा मंत्रालय का यह हाल है कि सेना की तरफ से कोई बयान भी नहीं दे सकते. जब देखो तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ही सेना की तरफ से बोलने चले आते हैं. हमें सेना के अधिकार के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए. जबकि पाकिस्तान की सेना के अधिकारी और उसके विदेश मंत्रालय दोनों बयान दिये जा रहे हैं.

अब देश को यह फैसला करना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है. क्या हमें सिर्फ पुलवामा का बदला लेना है या बीते तीस वर्षों में जान गंवाये सारे लोगों का बदला लेना है? यह बदला किस पैमाने पर लिया जायेगा? क्या हमारा एकमात्र लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के दौर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाये? क्या हमारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि भारत-पाक के बीच चल रहे एक अघोषित युद्ध को एक निर्णायक लड़ाई लड़कर खत्म कर दिया जाये? इन सब सवालों के जवाब हैं हमारे पास, लेकिन ये सिर्फ टोकनिज्म से हल नहीं होंगे, बल्कि निर्णायक युद्ध के फैसले से हल होंगे. नहीं तो फिर वही होगा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पुलवामा होगा, तो दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कोई और हमला. भारत को उतना जोर लगाना पड़ेगा, जितने से पाकिस्तान को यह समझ आ जाये कि यह रास्ता बहुत खतरे और जोखिम से भरा है और उसे छद्मयुद्ध को अब त्याग देना चाहिए. यह काम बातों से नहीं होगा, क्योंकि लातों का भूत पाकिस्तान बातों से नहीं मान सकता. पाकिस्तान को अगर युद्ध का इतना ही शौक है, तो मैं आज यह बयान देता हूं कि दो-दो हाथ के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी और सोवियत संघ की तरह पाकिस्तान भी इतिहास के कमोड में फ्लश हो जायेगा, वह बरबाद हो जायेगा.

आज कटोरा लेकर पाकिस्तान दुनियाभर से भीख मांग रहा है, उसकी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वह भारत पर हमले करे. पाकिस्तान ने यह बिल्कुल ही उपयुक्त समय चुना है भारत को छेड़ने का. वह सिर पर चढ़ गया है और अब उसे उतारने का समय आ गया है. बीते तीस साल से भारत की यह गलती रही है कि पाकिस्तान जैसे दो टके के देश को हमने सिर पर चढ़ा रखा है. लेकिन, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है. अब देश के नेतृत्व को डीमोनेटाइजेशन जैसी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को बंद करने पर मजबूर हो जाये. उसके बाद फिर चाहे दुनिया चें-चें करे तो करे, हमें कोई परवाह नहीं.

जनतंत्र और जन-घोषणापत्र

मनींद्र नाथ ठाकुर
एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू
manindrat@gmail.com

चुनाव का माहौल बनता जा रहा है. व्यवस्था के तौर पर जनतंत्र की जटिलता भी बढ़ती जा रही है. निश्चित रूप से जनतंत्र में बहुमत की सरकार बनती है. लेकिन, किस मुद्दे पर किस पार्टी का क्या विचार है और उनसे कितने लोग सहमत हैं, इसे जान पाना आसान नहीं है. जनतंत्र में जब राजनीतिक दलों का आविर्भाव हुआ, तो इन्होंने अलग-अलग मुद्दों पर अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, ताकि मतदाता उन विचारों को देखकर सहमति और असहमति का निर्णय ले सकें. दलों ने अपनी नीतियों-कार्यक्रमों से बहुमत को रिझाने का प्रयास किया. लेकिन, सूचना तकनीकी में भारी विस्तार के बाद क्या इसका कोई महत्व है या यह सिर्फ औपचारिकता मात्र ही है? क्या पार्टियां इसे लेकर गंभीर हैं? क्या जनता घोषणापत्र को गंभीरता से लेती है? क्या चुनाव पर इसका कोई प्रभाव पड़ता भी है?

आम तौर पर किसी पार्टी के घोषणापत्र को ठीक से पढ़ा जाये, तो हमें उसका जनाधार, उसकी विचारधारा और उसके कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है. जैसा हम जानते हैं 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' मार्क्स एवं एंगेल्स ने आंदोलन को दिशा देने के लिए लिखा था, एक बेहतरीन उदाहरण है घोषणापत्र का. उसे पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन समाज को कैसे समझता है और परिवर्तन के लिए किस तरह की योजना उसके विचारों में सही है. बाबा साहेब आंबेडकर का प्रसिद्ध लेख या गांधी का हिंद स्वराज औपचारिक तौर पर घोषणापत्र तो नहीं है, लेकिन आज भी जनांदोलनों को प्रभावित करता है. एक तरह से ये तीनों घोषणापत्र हैं, जो लोगों के स्वतंत्र और स्वाभाविक जीवन जीने में आनेवाली बाधाओं से मुक्ति के लिए आंदोलन की रूपरेखा देते है. इनमें दर्शन भी है, समस्याओं का विश्लेषण भी है और उनसे निकालने के लिए संघर्ष का आह्वाहन भी. राजनीतिक दलों का घोषणापत्र इतना गंभीर तो नहीं होता है और उनमें दर्शन से ज्यादा कार्यक्रम होता है, लेकिन यदि सही विश्लेषण करें, तो पार्टियों के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाता है.

भारतीय राजनीति में घोषणापत्र को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है. हर पार्टी के पास इसे लिखनेवालों की एक टीम तो जरूर रहती है, लेकिन है यह औपचारिकता मात्र ही. बहुत सी पार्टियां तो घोषणापत्र जारी ही नहीं करती हैं. उन्हें शायद यह लगता है कि इसका कोई मतलब इसलिए नहीं है कि मतदाता कभी उसे पढ़कर मत नहीं देता है. नतीजा है कि चुनाव में वादों की बरसात होती है. इन मौखिक वादों का कोई लेखा-जोखा चुनाव के बाद तो होता ही नहीं है. यदि जनता किसी नेता से कहती है कि आपने चुनाव के समय ऐसा कुछ कहा था, तो एक ही जवाब मिलता है कि यह तो कहने की बात है इसे लागू करना संभव नहीं है. वैसे भी आजकल पार्टियों द्वारा उनके घोषणापत्र में किये गये वादे ठीक उसी तरह हैं, जैसे साल के अंत में हिसाब-किताब देने कि लिए एक खास तरह का लेखा-जोखा तैयार किया जाता है.

यदि जन-घोषणापत्र हमारे पास हो, तो हम गांधी के स्वराज की कल्पना कर सकते हैं. इसे बनाये जाने की प्रकिया जितनी मुक्तिदायिनी होगी, उतनी ही मुक्तिदायिनी इसे लागू करवाने की प्रक्रिया भी होगी.

अब समय आ गया है कि चुनाव के समय जारी किये गये घोषणापत्रों को गंभीरता से लिया जाये. जनता को यह वैधानिक अधिकार दिया जाये कि इन घोषणाओं की जांच कर सके और इन्हें लागू करवाने के लिए उन्हें न्यायालय तक जाने की छूट मिले. इसे एक तरह से जनता और राजनीतिक दलों के बीच का कांट्रैक्ट समझा जाये और वादाखिलाफी को अपराध की श्रेणी में रखा जाये. कुछ समय पहले एक अच्छा प्रयोग देखने को मिला था, दो चुनावों के बीच 'वादा न तोड़' कार्यक्रम होता था, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वादा निभाने को कहा जाता था. बिहार के औरंगाबाद जिले के मुख्यालय में 'लोक संसद' के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ वादों को बड़े-बड़े होर्डिंग पर लिखकर चौराहों पर लगा दिया और रोज सुबह वहां जमा होकर उस पर चर्चा करने लगे. जनप्रतिनिधियों पर इसका बहुत असर पड़ा. सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिये भी समय-समय पर इन घोषणापत्रों के मूल्याकन का कार्यक्रम चलना चाहिए.

जनतंत्र के सफल होने की आवश्यक शर्त है कि जनता स्वयं भी अपना घोषणापत्र बनाये. हर चुनाव क्षेत्र में 'लोक संसद' हो, जो जन-संपर्क के माध्यम से लोगों की सार्वजनिक समस्याओं को लिपिबद्ध करे और उसे एक मांगपत्र का रूप दे. हमारे जनतंत्र की असली समस्या यह है कि चुनाव आते ही नये मुद्दे कृत्रिम तरीके से उछाले जाते हैं. इसलिए सरकारों और दलों का प्रचार बजट बढ़ता जा रहा है. ऐसे में जनता को अपनी समस्याओं को मजबूती से दलों के सामने रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और यह संघर्ष वैचारिक ज्यादा होगा. प्रचार कंपनियां लोगों की वैचारिक क्षमता को ही कुंद कर देती हैं. चुनाव बाद जब हमें समझ में आता है, तब तक देर हो चुकी होती है. यदि हम अपनी समस्याओं की सूची बनायेंगे, तो हमें बहकाना संभव नहीं होगा.

यदि ऐसा कोई घोषणापत्र हमारे पास हो, तो हम गांधी के स्वराज की कल्पना कर सकते हैं. इसे बनाये जाने की प्रकिया जितनी मुक्तिदायिनी होगी, उतनी ही मुक्तिदायिनी इसे लागू करवाने की प्रक्रिया भी होगी. फिर चुनाव का एजेंडा भी हमारा होगा और राजनीति भी हमारी होगी. पार्टियों और नेताओं का मुख्य काम हमारा प्रतिनिधित्व करना होगा, न कि हम पर राज करना. भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए जन-घोषणापत्र को जनजागरण के आंदोलनों में बदलने की जरूरत है.

आपके पत्र

अभिनंदन का अभिनंदन

आखिरकार पाकिस्तान की सरकार को मजबूरी में विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला करना पड़ा. वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उन्होंने शांति के लिए बातचीत के दरवाजे को खोलने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है. मगर सच तो यह है कि भारत की संभावित आक्रामक प्रतिक्रिया का भय ने पाकिस्तान को घुटनों के बल गिरने को मजबूर कर दिया है. बहरहाल, यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक विजय है. हमें याद है कि किस प्रकार कारगिल युद्ध के दौरान शत्रु देश द्वारा बंदी बनाये गये फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को भारत सरकार ने सफलतापूर्वक छुड़ाया था. वैसे, पाकिस्तानी सेना द्वारा मीडिया में पायलट की तस्वीर रिलीज करना और उनके हाथ बंधे वीडियो जारी करना 1949 के जिनेवा समझौते का उल्लंघन है. विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस दिलेरी से पाकिस्तानी सेना के सवालों का जवाब दिया उससे हम देशवासियों को उन पर गर्व है.

चंदन कुमार, देवघर

युद्ध की निरर्थकता पर बहस हो

युद्ध की कीमत दोनों गरीब जनता झेलती है. नेता तो केवल अपनी सत्ता के लिए पासे के रूप में युद्ध को एक तुरुप चाल के रूप में चलता है. इसमें यह मायने नहीं रखता कि कौन सत्ता में है या था. चुनाव के मद्देनजर इस तरह के छद्म युद्ध का वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कि सत्ता पक्ष अपनी कमियों को छुपा सके. यह खेल कांग्रेसियों के जमाने में भी खेला गया. वही मोदीजी भी खेल रहे हैं. वही नवाज शरीफ ने भी खेला. वही मियां इमरान भी खेल रहे हैं. सबसे दुखद बात यह है कि इसमें मरते आम आदमी हैं, चाहे भारत हो या पाकिस्तान. हथियार बनानेवाले देशों रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका, इजरायल आदि के खरबों रुपयों के युद्ध शस्त्र बिकते हैं और हम मूर्ख पड़ोसी यह नहीं समझते. युद्ध की निरर्थकता पर सभी देशों में तार्किक और सार्थक बहसें होनी चाहिए.

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

झूठ बोलने में पाकिस्तान आगे

भारतीय वायुसेना ने जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की, तो पाकिस्तान ने कोई नुकसान न होने का बहाना बनाया. लेकिन बुधवार की सुबह पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने का दुस्साहस किया तो भारतीय एयर फोर्स ने उसके एक फाइटर विमान को मार गिराया. भारत की इस कार्रवाई पर पाकिस्तान ने फिर वही पुराना राग अलापा, और कहा कि उसका कोई विमान नहीं गिरा है. उसने झूठा दावा किया कि भारत के दो पायलट उसकी हिरासत में है. दरअसल उसमें एक घायल पायलट उसका ही था. मजबूरन अपने बयान के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ी कि भारत का सिर्फ एक ही कमांडर उसके हिरासत में है. भारत के दो विमानों को मार गिराने का दावा भी पाकिस्तान का दूसरा झूठ साबित हुआ. उसकी सेना के प्रवक्ता ने बयान बदलकर भारत के दावों पर मुहर लगाने का काम जरूर किया है.

राजन कुमार, कांके, रांची

बोधि वृक्ष

मानवीय आधार

हम देखते हैं कि मानवीय आधार तथा उन्नत चेतन-वस्तु समूह में जड़-संघात और भाव-संघात दोनों ही हैं. दोनों के फल से वे क्रमशः प्रगति के पथ पर चलते रहते हैं. मनुष्य के दैनंदिन जीवन में हम लोग दोनों संघात देखते रहते हैं. दोनों हमें आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, किंतु ऐसा होने पर भी मनुष्य जाति को हम साधारणतः दो भागों में विभक्त देखते हैं. एक प्रकार के मनुष्य हैं जो केवल भाव-संघात का ही आह्वान करते हैं और द्वितीय श्रेणी के मनुष्य हैं, जो केवल जड़-संघात में ही लिप्त होना चाहते हैं. प्रथम श्रेणी को कह सकते हैं भाववादी, द्वितीय श्रेणी को भोगवादी. भाववादी और भोगवादी- दोनों ही साधक हैं, अंतर केवल लक्ष्य का है. जगत् में इनके दोनों पक्ष ही मानव-समाज की क्षति करते रहते हैं. मनुष्य को दोनों के बीच से आगे बढ़ना होगा, एक सामंजस्य रखकर, भाव को लक्ष्य बना जड़ के संघर्ष के मध्य होकर. भाव संघात में मनुष्य संपूर्णरूप से मानसिक तृप्ति (देह संपर्कित नहीं) के लिए कार्य करता है. वह मानसिक वस्तु चाहता है- यश पाने की आशा में वह कार्य करता है. इसलिए शुद्ध भाव-संघात संभवतः जड़-संघात से सूक्ष्म चीज है, किंतु इससे भी मनुष्य जाति का कितना कल्याण हो सकता है? शिक्षित तथा बुद्धिमान लोगों को भी देखते रहते हैं कि रुपये का लोभ नहीं रहने पर भी नाम-यश के लोभ से अन्य के प्रति कीचड़ उछालते रहते हैं. इस प्रकार का भाव-संघात क्या मनुष्य के मन को सूक्ष्मत्व की ओर ले जा सकता है? हम लोग देखते रहते हैं कि जड़ाश्रयी इज्मवाद के समर्थक दूसरे की युक्तिपूर्ण बात को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं और अपने युक्तिहीन आचार अनुष्ठान को आंख-कान बंद करके पकड़े रखना चाहते हैं. इस प्रकार के मनुष्य को जड़ की भावना बार-बार जड़ देह धारण करने के लिए बाध्य करती है. जहां ध्येय परमात्मा है, वहीं जीव की निरंकुश प्रगति होती रहती है. विषय सूक्ष्म और व्यापक होने के कारण मन भी सूक्ष्म और व्यापक होता है और इस व्यापकता के कारण मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है.

श्रीश्री आनंदमूर्ति

कुछ अलग

आप और बाजार दोनों खुश!

मुकेश कुमार
युवा रचनाकार
harpalmukesh@gmail.com

हमारे देश में हाट-बाजार की बात ही निराली होती है. अपनी जरूरत के सामान को देखना-परखना फिर मोलभाव और तब खरीदारी. आज बाजार की स्थिति बदलती जा रही है. हालांकि, बाजार का परंपरागत ढांचा अब भी बरकरार है. लेकिन बदलते वक्त ने इंसान के साथ कारोबार का भी स्वरूप बदला है. बाजार में बढ़ते मॉल का दिव्य मायाजाल, डिस्काउंट सेल, ऑनलाइन शॉपिंग ने ऐसे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. एंड्रॉयड मोबाइल और कंप्यूटर से वास्ता रखनेवालों को अब बाजार जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाजार खुद उनकी स्क्रीन में सिमटकर हाजिर हो गया है. आप कॉफी पीते रजाई में दुबककर भी अपनी शॉपिंग कर सकते हैं. किसी ने कहां सोचा था कि हर चीज ऑनलाइन हमारे घर पर मिलने लगेगी. आप खाने के शौकीन हों या पहनने के या फिर पढ़ने के, यहां सब कुछ उपलब्ध है. यह सुविधा भी है कि पसंद न आने पर वापस कर सकते हैं. अगर देखा जाये, तो जो मजा हमारे परंपरागत बाजार में ही है, हालांकि अब उसकी कमी खलती है. वहां हम हाथ में झोला और पॉकेट में लिस्ट लेकर जाते हैं, जबकि यहां ऑफर के लालच में अनावश्यक खरीदारी हो जाती है, जो तत्काल तो जरूरत की लगती है, पर बाद में बेकार हो जाती है. जिसके बगैर हमारा काम चल ही रहा था, वह एक क्लिक पर ऑर्डर होकर घर पहुंच जाता है. जोश में कुछ दिन उपयोग होता है, फिर बाद में वह चीज केवल शोपीस बनकर रह जाता है.

अप्रत्यक्ष रूप से बाजार आपसे आपका यह हक छीनता जा रहा है कि आपको क्या खरीदना है, बल्कि अपनी मार्केटिंग रणनीति में यह बात प्रमुखता से रखता है कि कौन सा उत्पाद किस तरह बाजार में बेचना है? धांसू विज्ञापन से किस तरह ग्राहक का मन मोहना है. यानी इस नये बाजार में आप अपनी जरूरत का सामान नहीं खरीदते, बल्कि बाजार अपने लक्ष्य के हिसाब से आपको अपना सामान बड़ी चालाकी से बेचता है. अब आपको सचेत रहना होगा कि आप जरूरत के हिसाब से सामान खरीदें, न कि आकर्षक सामान देखकर जरूरत पैदा कर लें. आज हमारे घर डाकिया आये या न आये, पर कोरियर वाला जरूर आ जाता है.

ऑनलाइन शॉपिंग करनेवालों की लत आज इतनी बुरी हो गयी है कि पंद्रह दिन भी नहीं हुए, पर उन्हें लगता है कि बहुत दिन हो गये कुछ शॉपिंग करनी चाहिए. यानी अपना मूड ठीक करने के लिए भी शॉपिंग होने लगी है. आखिर उनके शॉपिंग एप्स की भरी हुई विशलिस्ट किस दिन काम आयेंगी. आये दिन किसी न किसी 'डे' के बहाने बाजार उत्सव में बदल रहा है और जिसकी पॉकेट गर्म है, वे अपने पैसे लुटाकर रोज दीवाली और होली मना रहे हैं. कुल मिलाकर आज के बाजार में आपके चौकन्ना रहने की जरूरत है. खरीदारी में समझदारी का भी ध्यान रखना होगा. ऐसा है कि अब जेब सीधे नहीं काटा जाता, बल्कि आपको कोई प्रोडक्ट थमा दिया गया और कट गयी आपकी जेब. आप भी खुश और बाजार भी खुश!

देश दुनिया से

युद्ध से तबाह हो जायेगी भारत-पाक अर्थव्यवस्था

भारत और पाकिस्तान के बीच चार बार 1947, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हो चुका है. लेकिन आज अगर युद्ध होता है, तो यह दोनों के लिए विनाशकारी साबित होगा. भारत की आबादी का पांचवां हिस्सा और पाकिस्तान की आबादी का एक तिहाई हिस्सा बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं. युद्ध से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था तबाह होगी, बल्कि नागरिकों के जान-माल को भी क्षति पहुंचेगी. साथ ही अन्य वैश्विक शक्तियों के युद्ध में

INDEPENDENT

शामिल होने से यह कलह गहरा भी सकता है. यह दोनों देशों पर निर्भर है कि वे इस तनाव को कम करने के लिए संवेदनशीलता दिखायें. पाकिस्तानी सेना पहले से ही अखनूर, नौशेरा और पुंछ सेक्टरों में गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुकी है. जहां तक भारत की बात है, तो उसने भी सीमा पर सैनिकों की आवाजाही बढ़ा दी है. भारत के खिलाफ युद्ध के लिए इस्लामाबाद को चीन की सहायता लेनी होगी, क्योंकि वह कर्ज में डूबा हुआ है. युद्ध में चीन के शामिल होने से भारत की मुश्किल बढ़ जायेगी और इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं. ऐसे में किसी समझौते पर पहुंचने के लिए बयानबाजी को कम करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है.

सारोश बाना

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है